IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वैश्विक शासन में बहुपक्षवाद की भूमिका शंघाई सहयोग संगठन का विश्लेषण

प्रवीण कुमार यादव[1], डॉ अनुराधा राय[2]

शोध छात्र[1], असिस्टेंट प्रोफेसर[2]

राजनीति विज्ञान विभाग, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया उत्तर प्रदेश 277301।

सारांश

वैश्विक शासन का एक मूलभूत घटक, बहुपक्षवाद, संस्थागत ढाँचों के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए देशों को मिलकर काम करने की अनुमति देता है। एक प्रसिद्ध क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन के रूप में, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में यूरेशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। एससीओ के संस्थागत ढाँचे, रणनीतिक लक्ष्यों और संचालन प्रक्रियाओं के विश्लेषण के माध्यम से, यह शोध पत्र वैश्विक शासन में बहुपक्षवाद की भूमिका की जाँच करता है। यह आकलन करता है कि एससीओ बहुपक्षीय सहयोग को कितनी अच्छी तरह बढ़ावा देता है और एकपक्षवाद प्रवृत्तियों का प्रतिकार कैसे करता है, जो अक्सर क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालती हैं। यह शोधपत्र यूरेशियाई संदर्भ पर केंद्रित, अन्तरराष्ट्रीय संबंधों में एकपक्षीयता के मुद्दे की जाँच करता है। यह ऊर्जा असुरक्षा, आतंकवाद और भू–राजनीतिक विखंडन जैसे तात्कालिक वैश्विक मुद्दों से निपटने में बहुपक्षवाद के महत्व पर भी जोर देता है। इस अध्ययन का उद्देश्य बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने में एससीओ के लाभ और हानि का निर्धारण करना, क्षेत्रीय शासन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना और यह पता लगाना है कि यह वैश्विक शासन के व्यापक ढाँचों का समर्थन कैसे कर सकता है। यह जानने के लिए कि ये तत्व एससीओ के बहुपक्षीय एजेंडे को कैसे प्रभावित करते हैं, यह अध्ययन सदस्य देशों के बीच आंतरिक गतिशीलता, जैसे राजनीतिक निष्ठाएँ, आर्थिक हित और रणनीतिक प्राथमिकताओं, का भी अध्ययन करता है। एससीओ की सफल बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने की क्षमता, यूरेशियाई भू–राजनीति में एकपक्षवाद रणनीतियों के निरंतर उपयोग के कारण, और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली अन्तरराष्ट्रीय पहलों का समर्थन करने के लिए एससीओ जैसे क्षेत्रीय संगठनों की क्षमता, शोध प्रश्नों के मुख्य विषय हैं। यह शोध पत्र इस बात पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है कि एससीओ के विकास, संस्थागत संरचना और नीतिगत परिणामों का अध्ययन करके, क्षेत्रीय बहुपक्षवाद किस प्रकार एक स्थिरकारी शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है, जो लगातार खंडित होती जा रही विश्व व्यवस्था में एक स्थिरकारी शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है।

मुख्य शब्द: बहुपक्षवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा, अन्तरराष्ट्रीय सहयोग, आतंकवाद, वैश्विक शासन और शंघाई सहयोग संगठन

परिचय

वैश्विक शासन के एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में, बहुपक्षवाद ने लंबे समय से देशों को आर्थिक अस्थिरता, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों पर मिलकर काम करने की अनुमति दी है (रग्गी, 1992)। अतीत में, संयुक्त राष्ट्र, ब्रेटन वुड्स प्रणाली और क्षेत्रीय गठबंधन जैसे संगठन, जिनका उद्देश्य सहयोग को संस्थागत बनाना और एकपक्षवाद प्रभुत्व से बचना था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में अस्तित्व में आए (इकेनबेरी, 2001)। ये ढाँचे नियम–आधारित अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था के एक प्रतिबद्धता को दर्शाते थे और शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व, पारस्परिक सम्मान और साझा जिम्मेदारी के सिद्धांतों पर आधारित थे (केओहेन, 1984)।

विखंडन और एकपक्षवाद की वापसी आधुनिक वैश्विक व्यवस्था की तेजी से प्रमुख विशेषताएँ बनती जा रही है। शोधकर्ताओं का मानना है कि वैश्विक शासन में "स्पेगेटी बाउल" जैसा प्रभाव और समन्वय में कमी, अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के बीच परस्पर विरोधी मानदंडों और अतिव्यापी अधिदेशों के परिणामस्वरूप हुई है (बियरमैन एट अल., 2009; किम, 2020)। प्रमुख शक्तियाँ अक्सर अपने हितों को समूह के हितों से ऊपर रखती हैं, जिससे बहुपक्षीय संस्थाओं का क्षरण होता है और वैधता का संकट पैदा होता है (ली, 2025)। क्षेत्रीय संगठन इस बदलते परिवेश में सहयोग के वैकल्पिक स्थलों के रूप में अधिक प्रसिद्ध हो गए हैं क्योंकि वे भागीदारी के अधिक लचीले और स्थानीयकृत साधन प्रदान करते हैं (यूएन पीसमेकर, 2023)। इनमें से एक सबसे विशिष्ट यूरेशियाई पहल शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) है, जो अपने सदस्य देशों, जिनमें चीन, रूस, भारत और मध्य एशियाई गणराज्य शामिल हैं, के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा सहयोग को जोड़ता है। एससीओ जनसंख्या और भौगोलिक पहुँच दोनों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, और यह पूरे यूरेशिया में स्थिरता और बहुध्रुवीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है (एससीओ सचिवालय, 2024; सेज जर्नल्स, 2025)।

क्षेत्रवाद और बहुध्रुवीयता की गतिशीलता में बदलाव एससीओ के 1990 के दशक में एक सीमा–सुरक्षा तंत्र से एक व्यापक–आधारित बहुपक्षीय संगठन में परिवर्तन में परिलक्षित होता है (जू और माकेन्गो, 2021; प्रावदा, 2022)। यह बहुपक्षवाद का एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत करता है जो संप्रभुता, अहस्तक्षेप और सर्वसम्मति–आधारित निर्णय लेने पर जोर देकर पश्चिम–केंद्रित मानदंडों के विरुद्ध जाता है (एससीओ चार्टर, 2002; सीक आईएएस, 2024)। हालाँकि, इसकी प्रभावकारिता, आंतरिक एकता और वैश्विक शासन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता को लेकर अभी भी चिंताएँ हैं (ली, 2025; विजन आईएएस, 2025)।

यह शोध इस बात की बेहतर समझ प्रदान करता है कि क्षेत्रीय बहुपक्षवाद एससीओ को ऐतिहासिक और आधुनिक दोनों संदर्भों में रखकर वैश्विक शासन के भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से भू–राजनीतिक अस्थिरता और प्रतिस्पर्धा के समय में।

समस्या का विवरण

वैश्विक शासन के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के लिए एक बड़ा खतरा, एकपक्षवाद, अन्तरराष्ट्रीय संबंधों के बदलते क्षेत्र में तेजी से प्रचलित हो रहा है। इस बदलाव ने सहयोगात्मक तंत्रों को कमजोर किया है, बहुपक्षीय संस्थाओं की प्रभावशीलता को कम किया है, और आर्थिक एकीकरण, आतंकवाद–निरोध, क्षेत्रीय सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई जैसे जरूरी वैश्विक मुद्दों पर प्रगति को रोक दिया है। वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है, क्योंकि देश अपने सामरिक हितों को अपनी साझा जिम्मेदारियों से ऊपर रखते हैं, तथा अक्सर सहयोग के लिए स्थिरता, समानता और अन्य देशों पर विश्वास पर निर्भर रहते हैं।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जैसे क्षेत्रीय बहुपक्षीय मंच इस संबंध में अधिक प्रमुख हो गए हैं। हालाँकि, आंतरिक विषमताएँ, परस्पर विरोधी राष्ट्रीय एजेंडे और संस्थागत क्षमता का अभाव एससीओ के लिए सच्चे बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना मुश्किल बना रहा है। बहुध्रुवीय विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को पुनर्जीवित करने के एक मॉडल के रूप में एससीओ की क्षमता का आलोचनात्मक मूल्यांकन तत्काल आवश्यक है। एससीओ के कार्य, प्रभावकारिता और क्षेत्रीय बहुपक्षवाद के माध्यम से वैश्विक शासन को बढ़ाने की संभावनाओं की जाँच करके, यह अध्ययन इस कमी को पूरा करता है।

अनुसंधान के उद्देश्य

1. बहुपक्षवाद के ढांचे के भीतर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की संस्थागत संरचना और ऐतिहासिक विकास की जाँच करना।
2. क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग में एससीओ के योगदान का मूल्यांकन करना।
3. एससीओ के बहुपक्षीय संचालन को प्रभावित करने वाले भू–राजनीतिक कारकों और आंतरिक मुद्दों की जाँच करना।
4. बहु–शक्तियों वाले विश्व में बहुपक्षीय शासन के विभिन्न रूपों के लिए एक आदर्श के रूप में एससीओ की क्षमता की जाँच करना।

शोध प्रश्न

1. अपनी स्थापना के बाद से, एससीओ एक बहुपक्षीय संगठन के रूप में कैसे बदला है?
2. एससीओ अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और सुरक्षा जैसे मामलों पर उत्पादक सहयोग को कितना प्रोत्साहित करता है?
3. वे कौन से बाहरी और आंतरिक तत्व हैं जो एससीओ की बहुपक्षीय प्रभावशीलता को कमजोर करते हैं?
4. क्या वैश्विक शासन के निर्धारण में एससीओ पश्चिम के नेतृत्व वाले बहुपक्षीय संगठनों का एक अच्छा विकल्प है?

शोध की पृष्ठभूमि

कई देशों द्वारा बातचीत के माध्यम से वैश्विक मुद्दों पर बातचीत और सामूहिक निर्णय लेने के माध्यम से सहयोगात्मक भागीदारी को बहुपक्षवाद कहा जाता है। हालाँकि बहुपक्षीय सहयोग को संयुक्त राष्ट्र जैसी स्थापित संस्थाओं द्वारा लंबे समय से समर्थन दिया जाता रहा है, जो गरीबी, सुरक्षा और मानवाधिकार जैसे विषयों पर चर्चा को सुगम बनाती हैं, लेकिन बदलते भू–राजनीतिक परिवेश ने क्षेत्रीय संगठनों को जन्म दिया है जो सहयोग के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक ऐसा ही क्षेत्रीय बहुपक्षीय पहल है जिसका उद्देश्य पूरे यूरेशिया में स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। एससीओ एक सीमा–सुरक्षा तंत्र से विकसित होकर क्षेत्रीय शासन के लिए एक व्यापक मंच के रूप में विकसित हुआ है, जिसके सदस्य देश चीन, रूस, भारत और मध्य एशियाई गणराज्य हैं। यह अहस्तक्षेप, एक–दूसरे के प्रति सम्मान और आम सहमति निर्माण के मूल्यों को बढ़ावा देकर पश्चिमी उदारवादी ढाँचे से बाहर बहुपक्षवाद पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है।

स्रोत- Wikipedia Shanghai Cooperation Organisation (SCO) चित्र-1 (copypaste)

एकपक्षवाद के उदय ने अन्तरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों संस्थाओं की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है, जहाँ देश समूह के हितों की अपेक्षा अपने हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। एससीओ की सीमित संस्थागत क्षमता, रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और आंतरिक विषमताएँ महत्वपूर्ण बहुपक्षीय परिणाम देने की इसकी क्षमता पर संदेह पैदा करती हैं। इसके संदर्भ में, वैश्विक शासन में एससीओ की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा की जानी चाहिए और बहुध्रुवीय विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को पुनर्जीवित करने के एक मॉडल के रूप में इसकी क्षमता का आकलन किया जाना चाहिए।

बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने में शंघाई सहयोग संगठन की प्रभावशीलता

एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन जो यूरेशियाई भू–राजनीतिक परिवेश में बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने में तेजी से योगदान दे रहा है, वह है शंघाई सहयोग संगठन (SCO)। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और कई मध्य एशियाई देश SCO के सदस्य देशों में शामिल हैं। 15 जून, 2001 में स्थापित यह संगठन आर्थिक विकास, सांस्कृतिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में चर्चा, नीति समन्वय और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मंच प्रदान करता है (SCO चार्टर, 2002; प्रावदा, 2022)। पश्चिमी नेतृत्व वाले संगठनों के विपरीत, SCO का संप्रभुता, अहस्तक्षेप और सर्वसम्मति–आधारित निर्णय लेने पर जोर एक अद्वितीय बहुपक्षवाद मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है (सीक आईएएस, 2024)।

एससीओ की क्षेत्रीय समावेशिता बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाने में इसके प्रमुख लाभों में से एक है। एससीओ प्रमुख शक्तियों और छोटे देशों, दोनों को एकजुट करके रणनीतिक संतुलन और एक–दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है (जू और माकेन्गो, 2021)। इसके समान मताधिकार और घूर्णनशील अध्यक्षता यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि निर्णय समग्र रूप से समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कोई भी सदस्य एजेंडा को नियंत्रित नहीं करता है (एससीओ सचिवालय, 2024)। इसके अतिरिक्त, एससीओ विशिष्ट तंत्रों के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देता है जो परिचालन समन्वय और सदस्य विश्वास को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय आतंकवाद–रोधी संरचना (आरएटीएस), संयुक्त सैन्य अभ्यास और आर्थिक मंच (मनोरमा ईयरबुक, 2022; विकिपीडिया, 2024)।

एससीओ की अलग–अलग राजनीतिक संरचनाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को एकजुट करने की क्षमता एक और विशेषता है। इस संगठन ने अपने सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेदों के बावजूद, विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद–निरोध और क्षेत्रीय संपर्क के क्षेत्रों में, सहयोग के लिए एक कार्यात्मक ढाँचा बनाए रखा है (टेक्स्टबुक, 2024)। पर्यवेक्षक देशों और संवाद भागीदारों को शामिल करने के लिए इसके विस्तार से एक अधिक व्यापक बहुपक्षीय मंच के रूप में विकसित होने की इसकी क्षमता और भी स्पष्ट होती है (टीआरटी ग्लोबल, 2025)।

लेकिन एससीओ की बहुपक्षीय प्रभावशीलता भी गंभीर रूप से सीमित है। सदस्य देशों के बीच, विशेष रूप से चीन और छोटे मध्य एशियाई देशों के बीच, शक्ति असंतुलन मुख्य बाधाओं में से एक है। यह असमानता आम सहमति के विकास में बाधा डाल सकती है और रणनीतिक घर्षण पैदा कर सकती है (काकेशस एनालिस्ट, 2025)। इसके अलावा, सहयोग का दायरा द्विपक्षीय तनावों से सीमित है जो अक्सर एससीओ की कार्यवाहियों में भी दिखाई देते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव (दृष्टि आईएएस, 2024; इंडियाटीवी न्यूज, 2025)। क्षेत्रीय संकटों के जवाब में निर्णायक कार्रवाई करने की एससीओ की क्षमता, संयुक्त राष्ट्र के विपरीत, विवाद समाधान और प्रवर्तन के लिए मजबूत संस्थागत तंत्रों के अभाव के कारण सीमित है (टीआरटी ग्लोबल, 2025)।

इसके अलावा, नागरिक समाज की भागीदारी और पारदर्शिता के अभाव के कारण एससीओ की लोकतांत्रिक वैधता कमजोर हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के विपरीत, एससीओ में हाशिए पर पड़े समुदायों या गैर–सरकारी संगठनों के लिए निर्णय लेने में आधिकारिक माध्यमों का अभाव है, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर मुद्दों की अनदेखी करने वाली शीर्ष–स्तरीय नीतियाँ बन सकती हैं (जीएसडीआरसी, 2024य दृष्टि आईएएस, 2024)।

निष्कर्षतः, क्षेत्रीय बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने में एससीओ की उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, संस्थागत बाधाएँ, शक्ति असंतुलन और आंतरिक संघर्ष इसकी प्रभावशीलता को सीमित करते रहते हैं। वैश्विक शासन में अपनी भूमिका को बेहतर बनाने के लिए एससीओ को जवाबदेही और प्रवर्तन के लिए तंत्र बनाने, समावेशी संवाद को प्रोत्साहित करने और अपनी संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है। जैसे–जैसे दुनिया बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रही है, एससीओ का विकास बहुपक्षीय सहयोग के वैकल्पिक मॉडल बनाने में महत्त्वपूर्ण होगा।

क्षेत्रीय सहयोग पर एकपक्षवाद का प्रभाव और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में शंघाई सहयोग संगठन की क्षमता

आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय संबंधों में, एकपक्षीयता एक प्रमुख प्रवृत्ति बन गई है, जहाँ राज्य अपनी साझा जिम्मेदारियों की तुलना में अपने राष्ट्रीय हितों पर अधिक जोर देते हैं। इस परिवर्तन से पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थाएँ कमजोर हुई हैं, और अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक सहकारी ढाँचे अस्त–व्यस्त हो गए हैं (अशफाक, 2025)। अन्तरराष्ट्रीय विश्वास का टूटना, वैश्विक शासन का विघटन, और प्रतिद्वंद्वी शक्ति समूहों का उदय, एकपक्षीयता के कुछ सबसे स्पष्ट प्रभाव हैं (रेयेस, 2025)।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) इस संबंध में अन्तरराष्ट्रीय बहुपक्षवाद का एक क्षेत्रीय विकल्प प्रदान करता है। एससीओ में प्रमुख यूरेशियाई शक्तियों को एकजुट करने वाले एक मंच के रूप में संचार, एक–दूसरे के प्रति सम्मान और समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा देकर एकतरफा प्रवृत्तियों को संतुलित करने की क्षमता है। सहयोग का एक ऐसा मॉडल जिसका उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और रणनीतिक हितों को समायोजित करना है, संप्रभुता, अहस्तक्षेप और सर्वसम्मति–आधारित निर्णय लेने पर इसके जोर में परिलक्षित होता है (हान चुनलिन, 2025य एससीओ चार्टर, 2002)।

विश्वास का ह्रास एकपक्षवाद के प्रमुख प्रभावों में से एक है, जिससे देशों के लिए साझा उद्देश्यों पर बातचीत करना और भी मुश्किल हो जाता है। इस विश्वास को बहाल करने के लिए, एससीओ अपने लगातार शिखर सम्मेलनों, सहयोगात्मक अभ्यासों और क्षेत्रीय आतंकवाद–रोधी संरचना (आरएटीएस) जैसे संस्थागत साधनों के माध्यम से खुलेपन और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है (मनोरमा ईयरबुक, 2022)। हालाँकि, एससीओ की एकजुटता और प्रभावशीलता को सदस्य देशों के बीच आंतरिक प्रतिद्वंद्विता और विषमताओं, जैसे चीन का रणनीतिक प्रभुत्व या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, से चुनौती मिलती है (चौनल न्यूज एशिया, 2025; रेयेस, 2025)।

वैश्विक शक्ति गतिशीलता में परिवर्तन, जहाँ प्रभुत्वशाली देश क्षेत्रीय स्थिरता की बजाय अपने एजेंडे को प्राथमिकता देते हैं, एकपक्षीयता का एक और प्रभाव है। बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देकर और अपने सदस्यों के बीच प्रभाव वितरित करके, एससीओ का बहुपक्षीय ढाँचा इसे कम करने का लक्ष्य रखता है (अशफाक, 2025; ध्येय आईएएस, 2024)। इसकी संपर्क, व्यापार और सांस्कृतिक आदान–प्रदान पहलों का लक्ष्य एक अधिक लचीली और एकीकृत क्षेत्रीय व्यवस्था का निर्माण करना है। उदाहरण के लिए, चीन की 2025 की एससीओ अध्यक्षता ने एकपक्षीय व्यापार प्रथाओं के विकल्प के रूप में समावेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं, सतत विकास और विश्व व्यापार संगठन सुधार पर प्रकाश डाला (ग्लोबल टाइम्स, 2025)।

इन पहलों के बावजूद, एससीओ की क्षमता का अभी भी पूरी तरह से उपयोग नहीं हुआ है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता जैसे वैश्विक मुद्दों का पर्याप्त रूप से समाधान करने में इसकी असमर्थता, प्रवर्तन तंत्रों की कमी, सीमित संस्थागत क्षमता और नागरिक समाज के साथ कम संपर्क (ओईसीडी, 2025य एसीटीईडी, 2025) के कारण बाधित है। संयुक्त राष्ट्र के विपरीत, नागरिक समाज की भागीदारी के लिए औपचारिक मार्गों के अभाव के कारण एससीओ की लोकतांत्रिक वैधता और जमीनी मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता कमजोर होती है।

एससीओ को एक अधिक सक्रिय और समावेशी बहुपक्षीय संगठन के रूप में विकसित होना होगा जो न केवल एकपक्षवाद का विरोध करे, बल्कि वैश्विक शासन में भी महत्वपूर्ण योगदान दे, यदि उसे अपनी क्षमता का दोहन करना है। इस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए, संस्थागत तंत्रों को मजबूत करना, नागरिक समाज की सहभागिता में सुधार करना और क्षेत्रीय एकीकरण को गहरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्षतः, एससीओ क्षेत्रीय एकजुटता के माध्यम से बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने का एक रणनीतिक अवसर प्रदान करता है, हालाँकि एकपक्षवाद अभी भी अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के लिए खतरा बना हुआ है। आंतरिक संघर्षों को सुलझाने, अपने मानक प्रभाव को बढ़ाने और अपने उद्देश्यों को विश्व शांति, विकास और स्थिरता की सामान्य माँगों के साथ मिलाने की इसकी क्षमता ही यह निर्धारित करेगी कि यह कितना सफल होगा।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के दौरान भारत ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

चूँकि एससीओ के नियमों के अनुसार, संयुक्त घोषणापत्र के लिए पूर्ण सहमति आवश्यक है, इसलिए भारत के इनकार के कारण बैठक संयुक्त घोषणापत्र को अपनाए बिना ही समाप्त हो गई। रक्षा मंत्री ने दोहराया कि भारत ने "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" के सिद्धांत पर आधारित वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए एक समझौते पर पहुँचने का निरंतर समर्थन

किया है। यह "वसुधैव कुटुम्बकम" नामक प्राचीन भारतीय दर्शन पर आधारित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एससीओ वैश्विक जनसंख्या का 40% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% हिस्सा है (**visionias न्यूज टुडे 27 Jun 2025**)।

स्रोत– visionias न्यूज टुडे 27 Jun 2025 चित्र –2 (copypaste)

भारत के लिए एससीओ का महत्व– क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना: एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवाद–रोधी ढाँचा (आरएटीएस) आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सहायक हो सकता है। सामाजिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना: नवाचार और स्टार्ट–अप पर विशेष कार्य समूह और युवा वैज्ञानिक सम्मेलन जैसी पहलों के माध्यम से, एससीओ सहयोग को बढ़ावा देता है। उल्लेखनीय है कि नवाचार और स्टार्ट–अप पर विशेष कार्य समूह का प्रस्ताव भारत द्वारा रखा गया था (VisionIAS, 2025)।

क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना: एससीओ के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) का हिस्सा हैं। परिणामस्वरूप, भारत इन देशों की सहायता से लाभान्वित हो सकता है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) को संतुलित करने के लिए भी इस प्रकार की परियोजनाओं की आवश्यकता है। पश्चिमी प्रभुत्व वाली प्रभावशाली संस्थाओं का प्रतिसंतुलन: एससीओ ने व्यापार के लिए डॉलर के बजाय राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने का सुझाव दिया है। परिणामस्वरूप, पश्चिमी प्रभुत्व वाली संस्थाओं का प्रभाव कम हो सकता है। चीन और पाकिस्तान की निकटता, पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के प्रति चीन का उदार रवैया, एससीओ को एक पश्चिम–विरोधी संगठन के रूप में देखना, और अन्य कारक एससीओ में भारत के सामने आने वाली मुख्य बाधाएँ हैं (VisionIAS, 2025)।

सिद्धांत का विश्लेषण

एक सैद्धांतिक ढाँचे के रूप में, बहुपक्षवाद, बातचीत के माध्यम से आम सहमति और सामूहिक निर्णय लेने के माध्यम से साझा मुद्दों को हल करने के लिए राज्यों द्वारा मिलकर काम करने पर जोर देता है। बहुपक्षवाद, जो समानता, समावेशिता और एक–दूसरे के प्रति सम्मान के विचारों पर आधारित है, राष्ट्रीय स्वार्थ पर साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है और एकपक्षीयता का एक मानक विकल्प प्रदान करता है। क्षेत्रीय अस्थिरता, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक शासन के संदर्भ में बहुपक्षवाद को महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

यूरेशियाई भू–राजनीतिक वास्तविकताओं से प्रभावित बहुपक्षवाद का एक अनूठा उदाहरण शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) है। पश्चिम–केंद्रित संगठनों के विपरीत, एससीओ के सैद्धांतिक आधार संप्रभुता के सम्मान, अहस्तक्षेप और आम सहमति–आधारित सहयोग पर आधारित हैं। अपनी स्वतंत्रता का त्याग किए बिना, ये सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक संरचनाओं और रणनीतिक उद्देश्यों वाले सदस्य देशों को सहयोग करने और चर्चा करने में सक्षम बनाते हैं।

क्षेत्रीय व्यावहारिकता एससीओ के बहुपक्षवाद के सैद्धांतिक लाभों में से एक है। सार्वभौमिक मानकों को लागू करने के बजाय, यह सीमा सुरक्षा, आर्थिक संपर्क और आतंकवाद–निरोध जैसे क्षेत्रों में ठोस सहयोग पर जोर देता है। विशेष रूप से सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में, यह व्यावहारिक दृष्टिकोण सदस्य देशों के बीच परिचालनात्मक तालमेल और विश्वास को

बढ़ावा देता है। एक ऐसा मंच प्रदान करके जहाँ कोई एक शक्ति एजेंडे को नियंत्रित नहीं करती, एससीओ का बहुध्रुवीयता पर जोर, आधिपत्यवादी शासन मॉडल से दूर व्यापक सैद्धांतिक आंदोलन के साथ भी मेल खाता है।

हालांकि, एससीओ का बहुपक्षवाद सैद्धांतिक प्रतिबंधों के बिना नहीं है। नागरिक समाज की भागीदारी और संस्थागत प्रवर्तन तंत्र की कमी से इसकी लोकतांत्रिक वैधता और मानक गहराई पर सवाल उठाया जाता है। इसके अलावा, निर्णय लेने को विकृत किया जा सकता है और सदस्यों के बीच समानता का विचार शक्ति असंतुलन, विशेष रूप से चीन और रूस के रणनीतिक वर्चस्व से कमजोर हो गया है। इन असमानताओं के कारण, बहुपक्षीय सहयोग रणनीतिक संरेखण में बदलने का जोखिम उठाता है, जहां कमजोर राज्यों का परिणामों पर बहुत कम नियंत्रण हो सकता है।

एससीओ का मॉडल इन बाधाओं के बावजूद क्षेत्रीय बहुपक्षवाद पर विकसित हो रही बातचीत में योगदान देता है। यह सिद्ध करता है कि भू–राजनीतिक और सांस्कृतिक विशिष्टता पर आधारित वैकल्पिक ढाँचे वैश्विक शासन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार, एससीओ के सैद्धांतिक विश्लेषण द्वारा इस बात पर अधिक व्यापक विचार करने को प्रोत्साहित किया जाता है कि सहयोग, समावेशिता और साझा उत्तरदायित्व के अपने मूलभूत सिद्धांतों को कायम रखते हुए बहुपक्षवाद को विभिन्न क्षेत्रीय संदर्भों में कैसे समायोजित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

बहुपक्षवाद वैश्विक शासन का एक अनिवार्य घटक बना हुआ है, जो देशों को चर्चा, सहमति और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से साझा मुद्दों पर मिलकर काम करने के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है। यूरेशिया में स्थिरता, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन का एक उदाहरण शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) है। समान भागीदारी, संप्रभुता और अहस्तक्षेप पर इसका ध्यान एक अद्वितीय सहकारी मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है जो पारंपरिक पश्चिमी नेतृत्व वाले संगठनों से अलग है।

एससीओ ने आर्थिक संपर्क, आतंकवाद–रोधी समन्वय और क्षेत्रीय विश्वास को बढ़ावा देने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। एक पूर्णतः कार्यात्मक बहुपक्षीय निकाय के रूप में कार्य करने की इसकी क्षमता सदस्य देशों के बीच शक्ति असंतुलन, संस्थागत प्रवर्तन साधनों की कमी और आंतरिक राजनीतिक संघर्षों के कारण बाधित है। इसके अलावा, नागरिक समाज की लोकतांत्रिक वैधता और व्यापक विश्वव्यापी प्रभाव इसकी भागीदारी और पारदर्शिता की कमी के कारण सीमित हैं।

एससीओ को अपनी प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए इन व्यवस्थागत बाधाओं को दूर करके एक अधिक सक्रिय, समावेशी और जवाबदेह संगठन के रूप में विकसित होना होगा। वैश्विक शासन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, एससीओ को अपनी प्रभुत्व की पहुंच बढ़ानी होगी, समान भागीदारी को बढ़ावा देना होगा और अपनी संस्थागत क्षमता को मजबूत करना होगा। एससीओ जैसे क्षेत्रीय संगठन बहुपक्षीय सहयोग को पुनर्जीवित करने और एक अधिक लचीली एवं संतुलित अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि दुनिया बहुध्रुवीयता और बढ़ते एकपक्षवाद के दौर से गुजर रही है।

संदर्भ सूची (Reference)

1. Ruggie, J. G. (1992). Multilateralism: The anatomy of an institution. *International Organization*, *46*(3), 561–598. https://doi.org/10.1017/S0020818300027831
2. Ikenberry, G. J. (2001). *After victory: Institutions, strategic restraint, and the rebuilding of order after major wars*. Princeton University Press.
3. Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
4. Biermann, F., Pattberg, P., van Asselt, H., & Zelli, F. (2009). The fragmentation of global governance architectures: A framework for analysis. *Global Environmental Politics*, *9*(4), 14–40. https://doi.org/10.1162/glep.2009.9.4.14
5. Kim, R. E. (2020). Is global governance fragmented, polycentric, or complex? *International Studies Review*, *22*(4), 903–931. https://doi.org/10.1093/isr/viz052
6. Lee, S. (2025). *The impact of fragmentation on global governance*. Number Analytics. [Link not provided]
7. United Nations Peacemaker. (2023). *Partnerships with regional organizations*. [Link not provided]
8. Shanghai Cooperation Organisation Secretariat. (2024). *About SCO*. http://eng.sectsco.org
9. SAGE Journals. (2025). *The SCO amidst rising international tensions*. [Link not provided]
10. Fayyaz, S. (2025). SCO's counterterrorism strategy: A model for regional security cooperation. *Stratheia*. https://stratheia.com/scos-counterterrorism-strategy-a-model-for-regional-security-cooperation/
11. Li, S. (2025). Expand without dispersing: Institutional identity construction of the SCO. *International Politics*. https://link.springer.com/article/10.1057/s41311-025-00717-6
12. Noor, M. A. (2024). *Future of multilateral cooperation at SCO summit*. *Daily FT*. https://www.ft.lk/opinion/Future-of-multilateral-cooperation-at-SCO-summit/14-768161
13. Pravda, P. (2022). *The Shanghai Cooperation Organisation: Evolution, contemporary relevance and future trajectory*. Centre for Air Power Studies. https://capsindia.org/wp-content/uploads/2022/08/Pravda-P..pdf
14. SCO Charter. (2002). *Charter of the Shanghai Cooperation Organization*. https://www.mea.gov.in/Portal/LegalTreatiesDoc/000M3130.pdf
15. Seek IAS. (2024). *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*. Gokulam Seek IAS Academy. https://gokulamseekias.com/mains-c-a/shanghai-cooperation-organization-sco/
16. Vision IAS. (2025). *SCO Summit 2025: India's bold stand against terrorism reshapes regional diplomacy*. https://visionias.in/blog/current-affairs/sco-summit-2025-indias-bold-stand-against-terrorism-reshapes-regional-diplomacy
17. Wikipedia. (2024). *Shanghai Cooperation Organisation*. https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Cooperation_Organisation
18. Xue, Y., & Makengo, B. (2021). Twenty years of the Shanghai Cooperation Organization: Achievements, challenges and prospects. *Open Journal of Social Sciences*, *9*(10), 184–200. https://doi.org/10.4236/jss.2021.910014
19. Xinhua. (2025). *SCO bolsters security cooperation, economic integration among members*. *SCO China 2025*. https://www.scochina2025.org.cn/en/n3/2025/0314/c518818-20289590.html
20. Senadeera, M. (2023, April). *The role of multilateralism in global governance: An analysis of the United Nations*. University of Colombo.
21. Shanghai Cooperation Organisation. (2025). *The Shanghai Cooperation Organisation*. https://eng.sectsco.org
22. SCO China 2025. (2025). *China assumes the SCO rotating presidency for 2024–2025*. https://www.scochina2025.org.cn/en/
23. Caucasus Analyst. (2025). *SCO at a crossroads: India's waning influence amid tightening China–Pakistan axis*. https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13879-sco-at-a-crossroads-indias-waning-influence-amid-tightening-china-pakistan-axis.html
24. Drishti IAS. (2024). *Strengthening India–Pakistan relations and SCO*. https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/strengthening-india-pakistan-relations-and-sco

25. GSDRC. (2024). *Civil society legitimacy and accountability: Issues and challenges*. https://gsdrc.org/document-library/civil-society-legitimacy-and-accountability-issues-and-challenges/
26. Manorama Yearbook. (2022). *SCO and its Regional Anti-Terrorism Structure (RATS)*. https://www.manoramayearbook.in/current-affairs/india/2022/10/11/sco-rats-regional-anti-terrorism-structure.html
27. Testbook. (2024). *Regional Anti-Terrorist Structure: Objectives and structure*. https://testbook.com/ias-preparation/regional-anti-terrorist-structure-rats
28. TRT Global. (2025). *Can SCO take the lead in defusing India–Pakistan tensions?* https://trt.global/world/article/ff125ec76a6e
29. ACTED. (2025). *Strengthening institutions and civil society*. https://www.acted.org/en/what-we-do/our-programmes/strengthening-institutions-and-civil-society/
30. Ashfaq, W. (2025). *BRICS and SCO: A shift towards multipolarity?* PolicyEast. https://policyeast.com/brics-and-sco-a-shift-towards-multipolarity/
31. Channel News Asia. (2025). *China is set to host a record-sized SCO summit*. https://www.channelnewsasia.com/east-asia/china-shanghai-cooperation-organization-summit-leadership-rivalry-outcomes-5317231
32. Dhyeya IAS. (2024). *India's strategic vision for regional cooperation*. https://www.dhyeyaias.com/current-affairs/daily-current-affairs/indias-strategic-vision-for-regional-cooperation-insights-from-the-2024-sco-summit
33. Global Times. (2025). *China to enhance cooperation with other SCO member states*. https://www.globaltimes.cn/page/202508/1341859.shtml
34. Han Chunlin. (2025). *China's strategy for the SCO*. DK News. https://dknews.kz/en/articles-in-english/354042-china-s-strategy-for-the-sco-how-will-the
35. OECD. (2025). *Towards meaningful civil society participation at the international level*. https://www.oecd.org/en/publications/towards-meaningful-civil-society-participation-at-the-international-level_8ed04dc2-en.html
36. Reyes, A. (2025). *China's diplomatic clout at SCO summit*. *South China Morning Post*. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3322871/why-sco-summit-chinas-chance-assert-its-diplomatic-clout-amid-global-challenges
37. VisionIAS. (2025, June 27). *Daily current affairs*. VisionIAS. https://www.visionias.in/resources/daily_current_affairs_programs.php?type=1&m=06&y=2025